

प्रेषक,

राधा रतूड़ी
प्रमुख सचिव
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

सचिव
उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
देहरादून ।

कार्मिक अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक 13 जून, 2017

विषय:— उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को विभिन्न सुविधायें अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश दिनांक 30 मार्च, 2015 के द्वारा उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का वेतन निर्धारित किया गया है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को वेतन के अतिरिक्त विभिन्न सुविधायें निम्नवत अनुमन्य की जाती हैं।

(1) मकान किराया भत्ता— आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को किराया मुक्त आवास की सुविधा अनुमन्य होगी। आयोग के अध्यक्ष को राजकीय आवास की सुविधा उपलब्ध न होने पर प्रदेश शासन के अधीन समान वेतन के अधिकारी को अनुमन्य मकान किराया भत्ता देय होगा। अन्य सदस्यगण को राजकीय आवास की सुविधा उपलब्ध न होने पर राज्य सरकार के ₹ 10,000 ग्रेड वेतन अधिकारी को अनुमन्य मकान किराया भत्ता देय होगा।

(2) यात्रा भत्ता— आयोग के अध्यक्ष को प्रदेश शासन के अधीन समान वेतन के अधिकारी को वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-3 एवं सुसंगत आदेशों के द्वारा अनुमन्य यात्रा भत्ता अनुमन्य होगा। सदस्यगण को राज्य सरकार के ₹ 10,000 ग्रेड पे के अधिकारी को वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-3 एवं सुसंगत आदेशों के द्वारा अनुमन्य यात्रा भत्ता अनुमन्य होगा।

(3) अवकाश— अध्यक्ष एवं सदस्यगण को निम्नवत अवकाश अनुमन्य होगा:—

- (क) प्रत्येक 06 माह की सेवा के उपरान्त 15 दिवसों का उपार्जित अवकाश देय होगा।
- (ख) चिकित्सकीय आधार पर अथवा निजी कार्य हेतु प्रत्येक वर्ष की सेवा पर 20 दिवसों की दर से अर्धवेतन अवकाश देय होगा,
- (ग) चिकित्सकीय आधार पर अर्धवेतन अवकाश को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से पूर्ण वेतन अवकाश में परिवर्तित किया जा सकेगा बशर्ते कि वह सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त चिकित्सा प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित हो।

अवकाश स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी— अध्यक्ष को अवकाश स्वीकृत करने के लिये उनके नियोक्ताधिकारी सक्षम प्राधिकारी होंगे तथा सदस्यों को अवकाश स्वीकृत करने के लिये आयोग के अध्यक्ष सक्षम प्राधिकारी होंगे।

(4) चिकित्सा सुविधा— आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यगण को प्रदेश सरकार के अधीन कार्यरत समूह 'क' के अधिकारियों के समान चिकित्सा सुविधा अनुमन्य होगी।


(5) दूरभाष सुविधा— अध्यक्ष को कार्यालय तथा आवास, दोनों स्थानों पर टेलीफोन सुविधा प्रति टेलीफोन ₹ 25,000.00 वार्षिक तथा अन्य सदस्यगण को कार्यालय तथा आवास दोनों स्थानों पर प्रति टेलीफोन ₹ 20,000.00 वार्षिक अनुमन्य होगी।

(6) अन्य सुविधाओं का विनियमन— ऐसी सुविधायें जिनका उल्लेख उपर्युक्त सुविधाओं में नहीं है, के सम्बन्ध में यथा समय पृथक से निर्णय लिया जायेगा।

2— उपरोक्तानुसार निर्धारित की गयी व्यवस्थाओं को भविष्य में आवश्यकतानुसार और अन्य राज्यों में प्रचलित व्यवस्थाओं के अनुरूप समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।


3— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के अनुदान संख्या-09 के लेखाशीर्षक 2051-लोक सेवा आयोग-00-आयोजनेत्तर-103-कर्मचारी चयन आयोग-03-उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अन्तर्गत प्रासंगिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

4— यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या- 76/XXVII(10)/2017, दिनांक 12.06.2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 12- /XXX(4)/2017-03(06)/2015, तददिनांकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड ।
- 2— सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 3— स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 4— निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
- 5— वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- 6— वित्त अनुभाग-10, उत्तराखण्ड शासन।
- 7— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनील श्री पांथरी)
अपर सचिव।